जनसत्ता, 21-3-16, पृ 5

आम होगा आम, उप्र तोड़ेगा आम का रेकार्ड!

लखनऊ, 20 मार्च (भाषा)। माकूल मौसम की वजह से आम के पेड़ों पर आए जबर्दस्त 'बौर' से इस साल 'फलों के राजा' की अभूतपूर्व फसल होने की उम्मीद है। आम उत्पादकों का कहना है कि अगर सरकार 'दशहरी' आम की ब्रांडिंग के लिए उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम उठाए तो यह 'सोने पर सुहागा' होगा।

मैंगो ग्रोअर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष इंसराम अली ने रविवार को यहां बताया कि इस बार पेड़ों पर जबर्दस्त बौर (फूल) आया है। अगर हफ्ते भर तक मौसम इसी तरह सूखा रहा तो आम का उत्पादन 50 लाख मैट्रिक टन से अधिक हो सकता है, जो खुद में रेकार्ड होगा। पिछले साल 44 लाख मैट्रिक टन आम का उत्पादन हुआ था, जो अब तक का सर्वाधिक उत्पादन है। आम के पेड़ों पर इस बार इतना बौर आया है जितना कि पिछले 15-20 साल में नहीं देखा गया था। हाल-फिलहाल तो आंधी-पानी का दौर चलने का अनुमान नहीं है और अगर एक हफ्ते तक मौसम ऐसा ही रहा तो बौर मजबूत हो जाएगा और बागों में आम की फसल लहलहाएगी।

अली ने बताया कि आम उत्पादकों को सरकार की तरफ से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। अगर सरकार की मदद मिले तो सोने पे सुहागा हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि दशहरी की ब्रांडिंग के लिए उत्पादकों के स्तर पर तो प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार इस मौके की अनदेखी कर रही है। सरकार को 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' की तर्ज पर औद्यानिकी फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए राज्य स्तर पर कोई योजना चलानी चाहिए।

- आम के पेड़ों पर इस बार इतना बौर आया है जितना कि पिछले 15-20 साल में नहीं देखा गया था।
- पिछले साल 44 लाख मैट्रिक टन आम का उत्पादन हुआ था, जो अब तक का सर्वाधिक उत्पादन है।
- अगर हफ्ते तक मौसम इसी तरह सूखा रहा तो आम का उत्पादन 50 लाख मैट्रिक टन से अधिक हो सकता है।
- मैंगो ग्रोअर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आरोप लगाया कि आम उत्पादकों को सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है
- आम सरकारी अनदेखी के कारण वर्ष 2013 में करीब 12 हजार हेक्टेयर में फैले आम के बाग काट दिए गए।

जनसत्ता - 5 21-3-16

अली ने बताया कि मैंगो ग्रोअर्स एसोसिएशन की अरसे पुरानी मांग है कि सरकार के अधीन संस्था मंडी परिषद द्वारा निर्यात में खर्च होने वाले विमान किराए की मद में दिए जाने वाले अनुदान को 40 प्रतिशत से बढ़ा कर 80 प्रतिशत किया जाए। एक बार जब दशहरी आम विदेश के बाजार में पैठ बना ले तो फिर इस अनुदान को कम भी किया जा सकता है। सरकार अगर सेब की तरह आम की पैकेजिंग पर भी अनुदान दे तो इससे उत्पादकों की और मदद हो सकती है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा अनदेखी से परेशान होकर बड़ी संख्या में आम उत्पादकों ने यह काम छोड़ दिया है। उन्होंने आंकड़ा देते हुए बताया कि वर्ष 2013 में करीब 12 हजार हेक्टेयर में फैले आम के बाग काट दिए गए और उनके मालिकों ने उसकी जमीन को दूसरे कामों में इस्तेमाल कर लिया। लखनऊ के मलिहाबाद के अलावा सहारनपुर, उन्नाव, बाराबंकी, प्रतापगढ़, हरदोई, अमरोहा, मेरठ और बुलंदशहर की आम पट्टी में इस वक्त करीब ढाई लाख हेक्टेयर का रकबा है। जब तक फसल अच्छी हो रही है, तब तक तो ठीक है लेकिन अगर मौसम की मार पड़ी तो सरकार की अनसुनी से बेजार आम उत्पादक और भी लाचार हो जाएंगे।

जनसत्ता, 21 मार्च, 2016 9

फसल बीमा पर बैंकों, बीमा कंपनियों के साथ बैठक करेंगे मोदी

नई दिल्ली, 20 मार्च (भाषा)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह मुंबई में सभी बैंकों और बीमा कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन पर चर्चा होगी।

नई फसल बीमा योजना के तहत किसानों पर प्रीमियम का बोझ बीमा राशि के निचले स्तर यानी दो फीसद पर रखा जाएगा। साथ ही इस योजना के तहत दावों का निपटान जल्द से जल्द किया जाएगा। यह योजना जून में बुवाई की गई खरीफ फसलों के लिए एक अप्रैल से अस्तित्व में आएगी। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री के साथ यह बैठक नाबार्ड के कार्यालय में 22 मार्च को प्रस्तावित है। सूत्रों ने बताया कि ढाई घंटे की इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली और वित्त और कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऋण लेने और ऋण नहीं लेने वाले दोनों प्रकार के किसानों के लिए है। बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि अधिक किसानों को कैसे फसल बीमा योजना के तहत लाया जाए, जिससे 50 फीसद का लक्ष्य हासिल हो सके और अधिक से अधिक किसानों को बीमा सुरक्षा मिल सके।

दैनिक जागरण, पृ-4 21-3-16

मेले में महिला किसानों की दमदार उपस्थिति

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली : पूसा में कृषि मेले का आयोजन पिछले 44 वर्षों से लगातार हो रहा है, लेकिन इस बार का आयोजन अब तक हुए आयोजन से काफी भिन्न था। पहली बार इस मेले में देश के प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया और पहली बार कश्मीर से कन्याकुमारी व गुजरात से मेघालय तक के किसान नजर आए। किसानों की इतनी तादाद कभी नहीं पहुंची। इसमें महिला किसानों की अच्छी खासी तादाद नजर आई। इन महिलाओं को आमंत्रित किया गया है। इस आमंत्रण से महिला कृषक काफी खुश नजर आईं।

पूसा में पहली बार किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से मेले का आयोजन हो रहा है, अभी तक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से आयोजित होता रहा था। इस बार मंत्रालय के आयोजक होने के कारण पहले से अधिक संख्या में करीब 500 स्टॉल लगाए गए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से जुड़े विभिन्न संस्थानों के अलावा कई राज्यों ने भी अपने स्टॉल लगाए हैं। स्टालों पर विभिन्न राज्यों के कृषि उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। इन स्टालों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। विभिन्न राज्यों से आए कृषक इन स्टालों पर कृषि संबंधी जानकारी एकत्र कर रहे हैं। इन स्टॉलों पर कई फसलों के उन्नत किस्म के बीज भी बेचे जा रहे हैं। इनके बारे किसान जानकारी ले रहे हैं और खरीदारी भी कर रहे हैं।

- देश के कोने कोने से पहुंच रहे कृषक
- 44 वर्षों से किया जा रहा है मेले का आयोजन

उ.प्र. प्रभारी, समाचार पत्र यूनिट